

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

अजमेर

Rashtradoot

फोन:- 2627612, 2427249 फैक्स:- 0145-2624665

वर्ष: 30

संख्या: 40

प्रभात

अजमेर, मंगलवार 9 सितम्बर, 2025

आर.जे./ए.जे./73/2015-2017

पृष्ठ 6

मूल्य 2.50 रु.

कई देशों में ‘‘ जैनरेशन ज़ी’’ का असंतोष प्रस्फुरित हो रहा है

–डॉ सतीश मिश्रा–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 8 सितंबर। नेपाल में सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप, यूट्यूब और स्नैपचैट सहित, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद आज बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए, जिनमें सुरक्षा बलों के साथ झड़प में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और ३5० से ज्यादा घायल हो गए। घायलों में इसकी हालत नाजुक है।

हजारों प्रदर्शनकारी, जो खुद को ‘‘जनेरेशन ज़ी’’ कह रहे थे, सरकार के इस फैसले के खिलाफ काटमांडू में संसद भवन के पास इकट्ठा हुए। उन्होंने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लगे प्रतिबंध और सरकार में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया।

देश में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार के प्रति युवाओं में असंतोष और नाराज़गी अब प्रदर्शन के रूप में सामने आया है।

पिछले कुछ वर्षों में भ्रष्टाचार की कई घटनाएं, जिनकी सार्वजनिक रूप से और संसद में निरन्तर चर्चा होती रही है, लेकिन जिन पर कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, इन प्रदर्शनों को हवा देने का काम कर रही हैं।

इनमें वर्ष 2017 की एयरबस डील शामिल है, जिसमें नेपाल एयरलाइंस ने दो ए 330 वाइड–बॉडी जेट खरीदे थे। संविधान के तहत गठित

भारी भ्रष्टाचार के कारण ‘‘जैन ज़ी’’ को लगता है उसके साथ विश्वासघात हुआ है

- नेपाल में सड़कों पर उतरी जनता पर सरकार ने वॉटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, और फायरिंग की, जिसमें 20 लोग मर गए हैं और 350 से ज्यादा घायल हुए हैं।
- नेपाल में सड़कों पर उतरी युवा पीढ़ी भारी भ्रष्टाचार से पहले से ही गुस्से में हैं और सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाकर इसे भड़का दिया है।
- नेपाल में गत दिनों एयर बस खरीद में 10.4 मिलियन डॉलर का घोठाला हुआ, 5 साल जांच चली, कई आरोपी सामने आए पर कार्यवाही नहीं हुई।
- इतना ही नहीं, नेताओं के बच्चों के लम्ग़री जीवन के वीडियोज़ ने भी युवा असंतोष को भड़काया है।
- भारी भ्रष्टाचार से उभरे असंतोष ने श्रीलंका में तख्ता पलट किया और बांग्लादेश में भी जनता ने सड़कों पर आकर सरकार बदल दी।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि हर जगह युवा पीढ़ी का यह विरोध प्रदर्शन स्वप्रेरित है, जिसमें राजनैतिक दलों का कोई योगदान नहीं है।

निगरानी संस्था ‘‘कमीशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अब्यूज़ ऑफ् आर्थारिटी (सीआईएए)’’ द्वारा की गई पाँच साल लंबी जांच से गत वर्ष पता चला कि इस सौदे के कारण सरकारी खजाने को 1.47 अरब नेपाली रुपये (लगभग 10.4 मिलियन डॉलर) का नुकसान हुआ। जांच के बाद कई शीर्ष अधिकारियों को भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया।

2022 में श्रीलंका और 2024 में

बांग्लादेश में सरकारों को सत्ता से हटाने वाले आंदोलनों ने भी नेपाल के युवाओं को प्रेरित किया। इसके अलावा, फिलीपींस में नेताओं के बच्चों की ऐशो–आराम की ज़िंदगी की सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना और नेपाल के राजनेताओं के बच्चों के लम्ग़री जीवन को दिखाते हुए टिकटॉक पर वायरल हुए वीडियोज़ ने भी देश के युवाओं में आक्रोश को बढ़ावा दिया– खासकर एक ऐसे देश में, जहां प्रति

व्यक्ति आय सिर्फ 1३00 डॉलर प्रति वर्ष है।

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें टैक्स तो भरना पड़ता है, लेकिन उस पैसे के उपयोग का कोई स्पष्ट हिसाब नहीं दिया जाता।

प्रदर्शनों में स्कूल और कॉलेज के छात्रों की भारी भागीदारी देखी गई, जिनमें से कुछ ने तो स्कूल यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी। उत्पक्षदर्शियों का कहना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

टेलीग्राफ के संपादक संकर्षण ठाकुर का निधन

– जाल खंबाता –
– राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो –
नई दिल्ली, 8 सितम्बर। टेलीग्राफ के संपादक संकर्षण का सोमवार सुबह गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में कैंसर से निघन हो गया। वे 63 वर्ष के थे ठीक उसी उम्र में, जिस उम्र में उनके पिता और प्रसिद्ध पत्रकार जनार्दन ठाकुर का 1999 में निघन हुआ था। जनार्दन

- जाने माने पत्रकार जनार्दन ठाकुर के बेटे संकर्षण कैंसर से पीड़ित थे और गुरुग्राम के मेदान्ता अस्पताल में भर्ती थे।

ठाकुर उस समय फ्री प्रेस जर्नल के संपादक थे।

अंतिम संस्कार सोमवार शाम 5 बजे लोधी रोड शवदाहगृह में किया जाएगा।

संकर्षण ने रविवार को फेफड़ों के कैंसर की सर्जरी करवाई थी। उनके मित्र ए प्लस रक्त के डोनर की तलाश कर रहे थे ताकि उन्हें बचाया जा सके, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो सका।

‘‘ आधार कार्ड’’ स्वीकार्य होना चाहिये पहचान जताने के लिये

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुनः दोहराया, कि आधार कार्ड उन बारह दस्तावेजों में शामिल होना चाहिये, जो पहचान स्थापित करते हैं

– जाल खंबाता –
– राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो –
नई दिल्ली, 8 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण मामले में कहा कि, चुनाव आयोग को आधार कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार करना होगा और इसे उन 11 अन्य दस्तावेजों की सूची में शामिल करना होगा जिन्हें इस साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता दोबारा सत्यापन के लिए वैध माना गया है।

सोमवार सुबह अदालत में मौखिक आदेश जारी करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि आधार कार्ड को पहचान साबित करने के लिए 12वें दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, ताकि मतदाता सूची में किसी का नाम जोड़ा या हटाया जा सके।

पीलीभीत में नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ी

पीलीभीत, 08 सितंबर। नेपाल में बैन–भ्रष्टाचार के विरुद्ध संसद में घुसे युवाओं पर सेना की फायरिंग में 20 मौतों और 250 घायलों के घटे घटना क्रम के बाद पीलीभीत नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा को पर प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह

- नेपाल में हिंसक घटनाक्रम के बाद पीलीभीत प्रशासन ने सशस्त्र सीमा बल को बॉर्डर पर तैनात किया है।

एवं एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि घटना क्रम की जानकारी के बाद नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी सशस्त्र सीमा बल को सतर्क किया गया है। घटना क्रम का संज्ञान लेते हुए वहां के घटना क्रम पर दृष्टि बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। दोनों अधिकारियों ने पीलीभीत से सटी नेपाल सीमा पर किसी भी प्रतिबंध एवं कथर्पू लगाए जाने की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

–यादवेंद्र शर्मा–

जयपुर 8 सितंबर। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एसआई भर्ती–2021 पेपर लीक मामले में एकलपीठ के गत 28 अगस्त के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। इस मामले की अगली तारीख 8 अक्टूबर को रखी गयी है। अदालत ने इस मामले पर अंतरिम रोक लगाते हुए राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि, अगली सुनवाई तक इस भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाये, परंतु वह ट्रेनिंग में हिस्सा ले सकते हैं। जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश अमर सिंह व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। गौरतलब है कि एकलपीठ ने गत 28 अगस्त को याचिकाओं पर फैसला करते हुए भर्ती रद्द करने की मंशा जताते हुए राज्य सरकार को आरपीएससी में विस्तृत रिपोर्ट देने और उसके बाद आगामी कार्रवाई के आदेश दिए थे।

इस मामले में खंडपीठ ने यह सवाल उठाया कि, एकलपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गई याचिका में एस.ओ.जी. द्वारा गठित

राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बैंच ने 20 मिनट की सुनवाई के बाद एसआई भर्ती प्रकरण में सिंगल बैंच के 202 पेज के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई

स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एस.आई.टी.) की जो रिपोर्ट संलग्न की गई थी, उसे एडीजी एस.ओ.जी. द्वारा सत्यापित किया गया था या नहीं। अदालत ने अपील में आए याचिकाकर्ता की ओर से पूछा गया कि सिंगल बैंच में याचिका दायर करने वालों के पास एस.ओ. जी. की रिपोर्ट कहाँ से आई, क्योंकि यह रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं थी। इस प्रश्न को उठाते हुए अदालत में अपने आदेश में कहा कि, वह इस बिंदु पर संतुष्ट नहीं हुए कि यह रिपोर्ट कैसे अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई और इसकी वास्तविकता क्या है?

गौरतलब है कि एकलपीठ के समक्ष अदालती आदेशों पर इस मामले में एस.ओ.जी. द्वारा ही चार्जशीट और अपनी रिपोर्ट भी पेश की गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से भी जांच पड़ताल के संबंधित सभी दस्तावेज़ गृह विभाग की सिफारिश, एस.ओ.जी. की

- डबल बैंच ने स्ट्टे देते हुए सवाल उठाया है कि, याचिकाकर्ता ने जो एस.आई.टी. रिपोर्ट एकलपीठ में पेश की थी, वह रिपोर्ट वास्तविक है या नहीं?
- बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि एसआई भर्ती 2021 केस में हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत जिस एसआईटी रिपोर्ट पर डबल बैंच सवाल उठा रही है उसे ना तो कभी एसओजी ने झूठा बताया और ना ही राज्य सरकार या प्रतिवादी पक्ष ने इसे चुनौती दी, फिर खंडपीठ सवाल क्यों खड़े कर रही है।

एसआईटी की सिफारिश, मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश और गृह विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई सिफारिश के दस्तावेज अदालत में मुहैया करवाए गए थे। इसके अलावा इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता तथा महाधिवक्ता और प्रतिवादी पक्ष

‘सोशल मीडिया पर प्रतिबंध नहीं हटेगा’

नयी दिल्ली, 08 सितंबर। नेपाल में बड़े पैमाने पर हुए उपद्रव और 20 युवाओं की मौत के बाद भी प्रधानमंत्री के पी ओली ने सोशल मीडिया को खोलने को लेकर अपने रुख में किसी तरह के बदलाव का कोई संकेत नहीं दिया है।

कालिपुर ऑनलाइन के अनुसार, कांग्रेस की बैठक में सोशल मीडिया को तुरंत खोलने पर दबाव डाला गया, लेकिन प्रधानमंत्री ओली के अडियल रुख के कारण कोई फैसला नहीं हो सका। प्रधानमंत्री ओली अब भी सोशल मीडिया खोलने के पक्ष में नहीं हैं। इस आपात बैठक में शामिल एक

- नेपाल के प्रधानमंत्री के पी ओली ने अडियल रुख अपनाते हुए घोषणा की।

मंत्री के अनुसार, गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपना इस्तीफा सौंपते हुए सोशल मीडिया खोलने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित किया था। इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल ने भी सोशल मीडिया खोलने की ज़रूरत पर अपना रुख रखा, पर ओली अपने रुख पर कायम रहे।

सरकार ने सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं की जाँच के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया है। एक मंत्री के अनुसार, तथ्यों की जाँच और रिपोर्ट तैयार करने के लिए तत्काल एक जाँच समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।

जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनाव में 7५ प्रतिशत वोट मिले थे

सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों का अच्छा समर्थन मिला था, तथा गत तीन दशकों में इतने भारी मतों से कोई भी उपराष्ट्रपति नहीं जीता था

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 8 सितंबर। सूत्रों ने आज सुबह एन.डी.टी.वी. को जानकारी दी कि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के मंगलवार को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने की उम्मीद है, हालांकि, इस बार जीत का अंतर पिछले चुनावों जितना बड़ा नहीं होगा। एन.डी.ए. सूत्रों के अनुसार, इसीलिए हर वोट पर नज़र रखी जा रही है।

उपराष्ट्रपति का चुनाव सभी सांसद गुप्त मतदान से करते हैं। इसका मतलब है कि सांसद अपनी इच्छा से वोट डाल सकते हैं, हालांकि ज़्यादातर समय वे पार्टी लाइन पर चलते हैं। फिर भी, क्रॉस वोटिंग आम है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन रेड्डी की वायएसआर कांग्रेस और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री, के. चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति

भारत पर ‘‘ वो’’ असर नहीं हो रहा ट्रम्प की मीठी बातों का

जानकार सूत्रों का मानना है, भारत अभी सतर्क निगाहों से देख रहा है अमेरिका के हृदय परिवर्तन को

–जाल खंबाता–
–राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो–
नई दिल्ली, 8 सितम्बर। पिछले कुछ हफ्तों में भारत और अमेरिका के बीच बड़े तनाव, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ (शुल्क) लगाए जाने के बाद, अब जब राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति अपनी भाषा नरम की है, तो भारत ने इस बदलाव पर सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दी है।

ट्रंप ने शुक्रवार को वाइट हाउस में कहा कि भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है और दोनों देशों के बीच एक विशेष संबंध है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ‘‘महान प्रधानमंत्री’’ बताया और कहा कि वे हमेशा मोदी के मित्र रहेंगे। मोदी ने कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे ट्रंप की भावनाओं की ‘‘गहराई से सराहना करते हैं और उनका सम्मानपूर्वक उत्तर देते हैं।’’ हालांकि, नई दिल्ली के अधिकारियों का कहना है कि वे ट्रंप की टिप्पणी को सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं, लेकिन

- ट्रम्प ने शुक्रवार को पत्रकारों से वाइट हाउस में कहा था, अमेरिका व भारत के बीच विशेष रिश्ता है, तथा मोदी एक महान प्र.मंत्री हैं, तथा उनके सदा मित्र रहेंगे।
- मोदी ने प्रत्युत्तर में कहा, वे ट्रम्प की भावना को सकरात्मक मानते हैं, पर गौर-तलब बात है, कि मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया में ‘‘मित्र’’ कहकर सम्बोधित नहीं किया, जिसका मतलब यह लगाया जा रहा है, कि मोदी बड़ी सतर्कता से सम्बंधों की यात्रा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं।
- भारत सरकार के अनुसार ट्रंप के वाक्तव्य, इस बात का संकेत नहीं हैं, कि अमेरिका, भारत के सम्बंधों को अब नए नज़रिये से देख रहा है बल्कि भारत, वॉशिंगटन से मैत्रीपूर्ण संकेतों का इन्तज़ार करेगा, अमेरिका से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ने से पहले।

अतीत की तुलना में मोदी का रुख इस बार अलग था। इस बार उन्होंने ट्रंप को व्यक्तिगत मित्र कहकर संबोधित नहीं किया, जो यह संकेत देता है कि भारत वॉशिंगटन की ओर से और भी भरोसेमंद संकेत मिलने तक भारत रिश्तों को सामान्य मानकर नहीं चलेगा।

कि ट्रंप की हालिया टिप्पणी को भारत–अमेरिका संबंधों में नई शुरुआत के तौर पर नहीं देखा जा सकता। उनका कहना था कि वॉशिंगटन की ओर से और भी भरोसेमंद संकेत मिलने तक भारत रिश्तों को सामान्य मानकर नहीं चलेगा।

- इस बार भी साधारण अंक गणित के अनुसार, उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 881 वोटर हैं, तथा 391 मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होता है, तथा एन.डी.ए. के 425 सांसद हैं, लोकसभा व राज्यसभा में। अतः भाजपा के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है।

- पर, इस बार के.सी.आर. की पुत्री, के. कविता बगावत की मुद्रा में हैं, अतः हो सकता है कि के.सी.आर. की पार्टी, जिसने धनखड़ के चुनाव में एन.डी.ए. का साथ दिया था, इस बार मतदान में भाग न ले।
- नवीन पटनायक की बी.जे.डी. भी संभवतया गत चुनाव की भांति, एन.डी.ए. के उम्मीदवार को समर्थन देगी, पर इस बार स्थिति स्पष्ट नहीं है।

(बीआरएस) पहले भी कई बार भाजपा का समर्थन कर चुकी है। उदाहरण के लिए, 2022 में जगदीप धनखड़ ने तीन दशकों में सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, जब उन्हें विपक्षी

खेमे से भी समर्थन मिला था। इसमें वायएसआर कांग्रेस और उस समय ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के बीजू जनता दल (बीजद) का भी समर्थन शामिल था। धनखड़ को लगभग

75 प्रतिशत वोट मिले थे। इस बार भी क्रॉस वोटिंग की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में राज्यसभा में 239 और लोकसभा में 542 सांसद हैं। यानी कुल 781 सांसद वोट डालने के पात्र हैं और बहुमत का आंकड़ा 391 है। एनडीए के पास 425 सांसद हैं। इस हिसाब से भाजपा के उम्मीदवार, महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, साफ़ तौर पर विजेता दिखते हैं, जब तक कि भारी क्रॉस वोटिंग न हो। सूत्रों के अनुसार, भाजपा को 2022 की तरह औपचारिक गठबंधन से बाहर का समर्थन मिलने का भरोसा भी है। जगन रेड्डी की वायएसआर कांग्रेस पहले ही राधाकृष्णन को समर्थन दे चुकी है। वायएसआर कांग्रेस के पास कुल 11 सांसद हैं, राज्यसभा में सात और लोकसभा में चार। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संघ के सरकार्यवाह होसबोले जोधपुर एम्स में भर्ती

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की तबीयत बिगड़ गई। बीपी हाई होने पर उनको एम्स में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों की टीम की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। एम्स की सूचना पर पुलिस अधिकारी

- दोपहर में अचानक बीपी हाई हो जाने के कारण उन्हें भर्ती कराया गया।

भी मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार, 5 से 7 सितंबर तक जोधपुर में आर एस एस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई थी। संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत बैठक में शामिल होने के लिए 1 सितंबर को ही जोधपुर आ गये थे। अगले दिन 2 सितंबर को दत्तात्रेय होसबोले पहुंचे। दोनों लोगों ने 7 सितंबर तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक ली। बैठक के बाद, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CMYK

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

⊕

●●●●

CMYK

विचार बिन्दु

जहाँ चक्रवर्ती सम्राट की तलवार कुंठित हो जाती है, वहाँ महापुरुष का एक मधुर वचन ही काम कर देता है। –हरिऔध

उमर खालिद की जमानत

याचिका निरस्त होने के निहितार्थ

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नवीन चावला और शैलेंद्र कौर की खंडपीठ ने उमर खालिद और आठ अन्य लोगों के विरुद्ध यू ए पी ए और भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत चल रहे प्रकरण में जमानत याचिका 2 सितंबर 25 को खारिज कर दी। यह छठी बार था जब उमर खालिद की याचिका खारिज की गई। यहाँ यह लिखना प्रार्संगिक होगा कि बलात्कार के आरोप में दोषी और सजा याफ़ता आसाराम और बाबा राम रहीम अनेक पार पेरोल पर जेल से बाहर आ चुके हैं।

आइए, देखते हैं, उमर खालिद और आठ अन्य लोगों पर वास्तव में क्या आरोप हैं? इनके विरुद्ध फरवरी,2020 में दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने का आरोप है। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे। इन पर यू ए पी ए भी लगाया गया है। जमानत याचिका खारिज करने वाले 1३3 पृष्ठों के निर्णय में न्यायालय ने विस्तार से यह लिखा है कि अभियुक्तों ने आतंकवादी गतिविधियाँ फैलाने के लिए सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र किया, देश को विदेशों में बदनाम किया एवं सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया । यह उल्लेखनीय है कि उमर खालिद और आठ अन्य लोग गत 5 वर्षों से जेल में बंद हैं। इनके विरुद्ध अभी तक न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ भी नहीं हो पाई है । अब तक छह बार इनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनेक बार यह कह चुके हैं कि न्यायिक प्रकरणों में जेल अपवाद है और बेल यानि जमानत ,नियम । उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर के यह स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि यह सिद्धांत सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू नहीं होता है । प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने ‘इंडियन एक्सप्रेस’ में दिनांक 5 सितंबर 2025 को प्रकाशित अपने लेख में यह स्पष्ट बताया है कि मुंबई में जनवरी, 2020 में आयोजित एक बड़े सम्मेलन में जो बातें उमर खालिद ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कही थीं, उस सम्मेलन में वह भी मौजूद थे। उन्होंने भी लगभग वही बातें कही थीं । अतः, उन्हें भी जेल में होना चाहिए था। उन्हें तो एक बार भी पूछताछ तक के लिए नहीं बुलाया गया। इस सम्मेलन में लगभग एक लाख व्यक्ति उपस्थित थे। अतः एक संदेश तो यह गया है कि देश के सभी नागरिकों के लिए कानून समान रूप से लागू नहीं होता। यदि आप बहुत संख्यक वर्ग से हैं तो कानून एक तरह से लागू होगा और यदि अल्पसंख्यक वर्ग से हैं तो वही अलग तरह से लागू होगा ।

इसी प्रकार यदि आप सरकार समर्थक विचार के हैं तो आप के साथ उदरता बरती जाएगी और यदि विरोधी विचार के हैं तो वही कानून पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। यह भारतीय संविधान की मूल भावना के विपरीत है, जिसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि देश के सभी नागरिकों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा का भेदभाव के सुनिश्चित कराया जाएगा। उमर खालिद से संबंधित यह निर्णय संविधान की मूल भावना पर गहरी चोट करता है। यह प्रकरण उसी प्रकार इतिहास में कुख्यात होगा जिस प्रकार एडीएम जबलपुर वाला मामला, जिसका निर्णय आपातकाल में दिया गया था और जिसे आज भी नागरिक अधिकारों के हनन के फैसले के रूप में याद किया जाता है।

अभियुक्त के वकीलों ने जब न्यायालय का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि 5 वर्ष तक बिना ट्रायल के उनके पक्षकार जेल में बंद हैं और इस कारण उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है तो न्यायालय ने कहा कि प्रकरण सामान्य गति से चल रहा है और न्याय मिलेगा । यह समझ से परे है कि 5 वर्ष तक ट्रायल प्रारंभ न होना क्या सामान्य गति है? तो फिर, असामान्य गति किसे कहेंगे?

इस निर्णय से दूसरा संदेश यह जाता है कि यदि आप सरकार की विचारधारा के समर्थक है तो आपको कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा और आपके नागरिक अधिकारों की रक्षा भी होगी, किंतु यदि आप सरकार के किसी भी निर्णय के विरुद्ध खड़े हैं तो फिर न केवल सरकार बल्कि न्यायापालिका भी आपके अधिकारों का हनन करने के लिए तत्पर दिखाई देगी। माना जाता है कि सरकार जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करे तो न्यायापालिका उसकी रक्षा के लिए आगे आएगी। इस प्रकरण में तो ऐसा लगता है, सरकार के दमनकारी रवैये पर न्यायालय ने भी एक प्रकार से न्यायिक मुहर लगा दी है। ऐसे में सामान्य नागरिक क्या करेगा और कहा जाएगा ? संदेश स्पष्ट है, आपको जो भी विचारधारा हो उसे आप अपने तक सीमित रखिए उसे सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त मत करिए और भूल कर भी सरकार की किसी नीति या निर्णय की सार्वजनिक रूप से आलोचना मत करिए ।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में कई बार कहा है कि केवल अपने विचार को अभिव्यक्त करना, ब्हाट्सएप पर संदेश भेजना, कविता लिखना, नारा लगाना या सरकार कके किसी कानून के विरोध में प्रदर्शन करने को आतंकवादी गतिविधि नहीं माना जा सकता । इसी तर्क के आधार पर अनेक आरोपियों को जमानत भी मिली है। यह जानना भी रोचक है की उमर खालिद वाले प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में 14 बार तरीख बदली गई । कुछ न्यायाधीशों ने अपने आपको इसकी सुनवाई से अलग कर लिया । इसके कारण सरकार आरोपियों को जेल में रखने में सफल हुई। होना तो यह चाहिए था कि जो व्यक्ति बिना दोष सिद्ध हुए जेल में बंद हो उसके प्रकरण का निस्तारण शीघ्र किया जाना चाहिए था।

उमर खालिद और उसके साथियों का दोष केवल यह था कि उसने सी ए ए के विरुद्ध प्रदर्शन में बैठे हुए लोगों का साथ दिया और उनके समर्थन में भाषण दिए और उसने इसे मुसलमान विरोधी बताया।

जब दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुरलीधर ने भडकाऊ भाषण न्यायाधीश मुरलीधर ने भडकाऊ भाषण

जब न्यायपालिका भी अपने आपको स्वतंत्र अनुभव नहीं करेगी एवं दबाव में काम करती दिखाई देगी तो फिर लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने की आशंका उत्पन्न होती है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत को एक कमजोर लोकतंत्र के रूप में देखा जाने लगा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैमाने पर भारत दुनिया के नीचे पायदान वाले देशों में सम्मिलित हो गया है।

देने और गोली मारने के लिए उकसाने वाले मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा नेता कपिल मिश्रा एवं अन्य लोगों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज करने के आदेश दिए तो रातों-रात न्यायाधीश मुरलीधर का स्थानांतरण दिल्ली से बाहर कर दिया गया ताकि वह इस प्रकरण को न सुन सकें न उसके ऊपर कोई निर्णय दे सकें। यही नहीं, वरिष्ठ होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी इन्हें नहीं बनाया गया ।

इससे यह संदेश दिया गया कि जो न्यायाधीश सरकार की इच्छानुसार सत्ताधारी लोगों के पक्ष में निर्णय नहीं देगे उनके प्रति सरकार कड़ा ख़्त अपनाएगी ऐसा हमने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अकील अहमद कुरैशी के मामले में भी देखा था जिन्हें योग्य और वरिष्ठ होने के बावजूद सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बनाया गया। न्यायाधीश पंचोली की हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति कर दी गई जबकि इसका स्पष्ट विरोध सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश एवं कॉलेजियम की सदस्य न्यायमूर्ति नागरत्ना ने किया था। उन्होंने अपनी विमत वाली टिप्पणी को सार्वजनिक करने हेतु कहा था किंतु ऐसा नहीं किया गया ।

जब न्यायपालिका भी अपने आपको स्वतंत्र अनुभव नहीं करेगी एवं दबाव में काम करती दिखाई देगी तो फिर लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने की आशंका उत्पन्न होती है। यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत को एक कमजोर लोकतंत्र के रूप में देखा जाने लगा है।अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पैमाने पर भारत दुनिया के नीचे पायदान वाले देशों में सम्मिलित हो गया है।

न्यायपालिका का समझौतावादी दृष्टिकोण बिहार के एस आई आर (मतदाता सूचियों का स्पेशल इंटरसिव रिवीजन) वाले प्रकरण से भी स्पष्ट होता है। इसके कारण होने वाली अनेक समस्याओं को प्रभावी रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करने के बावजूद इसे अभी तक निरस्त नहीं किया गया। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कोई अंतिम स्पष्ट आदेश जारी करते हैं अथवा नहीं ? यदि ऐसा नहीं किया गया तो सितंबर के अंत में चुनाव आयोग बिहार के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर देगा और उसके बाद न्यायालय का दखल वैसे ही संभव नहीं हो पाएगा ।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे प्रमुख मौलिक अधिकार है जो लोकतंत्र का प्रमुख स्तंभ भी है । इसी अधिकार पर कार्यपालिका द्वारा लगातार प्रहार किया जा रहा है। कुछ न्यायाधीशों ने साहस करके समय-समय पर इस अधिकार की रक्षा करने का प्रयास भी किया है। जिस प्रकार से न्यायिक नियुक्तियों में समझौता किया जा रहा है उससे तो लगता है आने वाले समय में न्यायपालिका, कार्यपालिका एवं विधायिका का इच्छा अनुसार ही काम करता हुई दिखाई देगा। यह लोकतंत्र के लिए घातक होगा और फिर देश अधोषित आपातकाल की स्थिति में पहुंच जाएगा।

सभी सरकारी और संवैधानिक संस्थाओं में तो सरकार ने अपनी पसंद के लोगों को नियुक्तियां पहले ही कर रखी हैं । केवल न्यायपालिका कभी कभार स्वतंत्र दिखाई देती है ।

उमर खालिद की जिस प्रकार से जमानत याचिका रद्द की गई है, उसे देखते हुए यह आशंका हो गई है कि अब नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की कोई संस्था साहस ही नहीं करे। यह देश के लिए चिंता का विषय है। ऐसा सामान्यतया "banana republic" देशों में होता है । भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां का संविधान सर्वश्रेष्ठ है। यह 145 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है । इसे बचाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है क्योंकि गणतंत्र में उसी की सक्ष सर्वोच्च है। असहमति लोकतंत्र की आत्मा है, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सबसे अधिक उन्हीं की है। आशा है, उमर खालिद और उसके आठ साथी शीघ्र जेल से बाहर आएंगे और सच्चे देशभक्त की तरह देश को आगे बढ़ाने में अपना पूरा योगदान देंगे, अहिंसक जन आंदोलन चलाने को किसी भी रूप में आतंकवादी गतिविधि नहीं माना जाना चाहिए। लोगों को संगठित करना और प्रदर्शन करना गांधी, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉ की आर अंबेडकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने ही सिखाया है। आशा है संवैधानिक संस्थाएं, विशेषकर न्यायपालिका, पूरी निष्पक्षता और निर्भीकता से नागरिकों के संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करके लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का कार्य करेंगी।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



अशोक कुमार

आज की दुनिया में शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ गया है, और शिक्षण संस्थानों का बुनियादी ढांचा इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी शिक्षण संस्थान की स्थापना से पहले यह सुनिश्चित करना कि उसके पास आवश्यक बुनियादी ढांचा है, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। भारत में नए शिक्षण संस्थानों की स्थापना एक गंभीर मुद्दा है। अक्सर देखा जाता है कि नए स्कूल, कॉलेज, और विश्वविद्यालय बिना पर्याप्त बुनियादी ढांचे के ही खोल दिए जाते हैं, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए, यह अत्यंत आवश्यक है कि नए संस्थान तभी स्थापित किए जाएं जब उनके पास सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों। एक शिक्षण संस्थान केवल इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसा वातावरण है जहाँ ज्ञान का आदान-प्रदान होता है।

एक अच्छी तरह से बनी हुई इमारत, हवादार क्लासरूम, और पर्याप्त रोशनी छात्रों को सीखने के लिए एक बेहतर माहौल प्रदान करते हैं। यह छात्रों की एकाग्रता और शिक्षकों के प्रदर्शन को भी बढ़ाता है।

आज के समय में सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है। विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं आवश्यक हैं। बिना इनके, छात्र केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रह जाते हैं और उन्हें व्यावहारिक अनुभव नहीं मिल पाता।

वर्तमान स्थिति और समस्याएं वर्तमान में, भारत में शिक्षा क्षेत्र में मात्रा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, जबकि गुणवत्ता को अक्सर नजरअंदाज किया जाता है।

अधुरी इमारतें: कई संस्थानों के पास पूरी तरह से बने हुए भवन नहीं होते। क्लासरूम, लाइब्रेरी, और प्रशासनिक कार्यालय आधे-अधूरे होते हैं।

शिक्षकों की कमी: सबसे बड़ी चुनौती योग्य और पर्याप्त शिक्षकों की कमी है। कई संस्थान सिर्फ कागजों पर ही चलते हैं, और वहां पढ़ाने वाले शिक्षक या तो अनुपलब्ध होते हैं या फिर उन्हें सही वेतन नहीं मिलता, जिससे उनका मनोबल कम होता है।

प्रयोगशाला और पुस्तकालय का अभाव: विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए प्रयोगशालाएं और सभी विषयों के लिए पुस्तकालय अत्यंत आवश्यक हैं।

बिना पर्याप्त उपकरणों और किताबों के, छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान मिलता है, जो उनके भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं होता।

कर्मचारियों की कमी: शिक्षण संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है, जिनका अक्सर अभाव होता है।

यह स्थिति न केवल छात्रों के भविष्य को खतरे में डालती है, बल्कि पूरे शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता को भी कम करती है।

वर्तमान में प्रमुख समस्याएं भारत में कई नए शिक्षण संस्थान बिना पर्याप्त तैयारी के खोले जाते हैं। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:

निजीकरण और मुनाफाखोरी: कई बार, निजी संस्थान शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में देखते हैं, और जल्द से जल्द मुनाफा कमाना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में, वे लागत कम करने के लिए बुनियादी ढांचे पर खर्च नहीं करते।

सरकार की हिलाई: नियामक निकाय (जैसे UGC और AICTE) द्वारा बनाए गए नियमों का सख्ती से पालन नहीं कराया जाता। निरीक्षण अक्सर कागजी कार्यवाही तक ही सीमित रह जाते हैं।

राजनीतिक दबाव: कुछ मामलों में, राजनीतिक प्रभाव के कारण भी संस्थानों को बिना पर्याप्त सुविधाओं के ही मान्यता मिल जाती है।

समाधान: सम्पूर्ण बुनियादी ढांचे के बाद ही स्थापना समस्या का समाधान करने के

लिए, सरकार और नियामक निकायों को कुछ कड़े कदम उठाने होंगे:

सख्त नियम और उनका पालन: नए शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने से पहले सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचों का भौतिक सत्यापन (physical verification) अनिवार्य किया जाना चाहिए। शिक्षकों की भर्ती: यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी संस्थान को मान्यता देने से पहले, वहाँ पर्याप्त संख्या में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी हो। लोगों को भी इस विषय पर जागरूक होना चाहिए। छात्रों और अभिभावकों को किसी भी संस्थान में दाखिला लेने से पहले उसके बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं की जांच करनी चाहिए।

सरकार और नियामक निकाय (Regulatory Bodies) नए शिक्षण संस्थानों को तभी लाइसेंस या मान्यता दें, जब वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करें:

भवन और क्लासरूम: संस्थान के पास सभी आवश्यक क्लासरूम, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, और प्रशासनिक कार्यालय पूरी तरह से तैयार हों।

योग्य शिक्षक: नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो और सभी शैक्षणिक हदों पर योग्य और अनुभवी शिक्षक नियुक्त हों। शिक्षकों की संख्या छात्रों के अनुपात (Student-Teacher Ratio) के अनुसार होनी चाहिए।

बिना उचित बुनियादी ढाँचे के योग्य शिक्षक उस संस्थान से जुड़ने में हिचकिचाते हैं। एक अच्छी तरह से

सुसज्जित संस्थान, जिसमें शिक्षकों के लिए स्टाय रूम, लाइब्रेरी और अन्य सुविधाएं हों, उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं।

पूर्ण कर्मचारी: प्रशासनिक और सहायक कर्मचारियों की भर्ती भी पूरी हो चुकी हो, ताकि संस्थान का दैनिक कामकाज सुचारू रूप से चल सके।

आधुनिक प्रयोगशालाएं: विज्ञान, इंजीनियरिंग, और अन्य विषयों के लिए अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित प्रयोगशालाएं हों।

पुस्तकालय और संसाधन: एक विशाल और सुव्यवस्थित पुस्तकालय हो जिसमें पर्याप्त क्लाउड, जर्नल्स और डिजिटल संसाधन उपलब्ध हों।

छात्रों के समग्र विकास के लिए: बुनियादी ढाँचे में सिर्फ क्लासरूम ही नहीं, बल्कि खेल के मैदान, कैफेटेरिया, सभागार और अन्य गतिविधियां शामिल होती हैं। ये सभी छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक हैं।

संक्षेप में, "शैक्षणिक संस्थान बुनियादी ढाँचे स्थापित करने के बाद ही खोले जाएं" का सिद्धांत केवल एक सुझाव नहीं है, बल्कि एक आवश्यकता है। यह शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने, छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने, और भारत को एक मजबूत ज्ञान अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महत्वपूर्ण है।

—अशोक कुमार, पूर्व कुलपति, कानपुर एवं गोरखपुर विश्वविद्यालय; पूर्व विभागाध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

ब्रॉडगेज विद्युतीकरण और सौर ऊर्जा क्षेत्र में भी प्रगति के पथ पर अजमेर मंडल

अजमेर मंडल पर ब्रॉडगेज के सभी खंडों पर 100 प्रतिशत विद्युतीकरण पूर्ण

■ वर्तमान में अजमेर मंडल के अंतर्गत 110 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन विद्युत इंजन के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे न केवल इंधन की बचत हो रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला है

■ अब तक मंडल में कुल 1030.21 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है

ऊर्जा दक्ष व इको फ्रेंडली होता है। जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त में मददगार साबित होता है साथ ही आयातित ईंधन पर निर्भरता भी कम होती है। अजमेर मंडल ने विगत समय में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। मंडल पर अब तक कुल 359० किलोवॉट पावर क्षमता के सोलर पैनल स्थापित किये गये हैं। इनसे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 में 72.3 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 34 लाख रुपये के राजस्व की बचत भी हुई है।

एनआईआरएफ-2०25 रैंकिंग में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय को 89वां स्थान मिला

यह स्थान उच्च शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में भारत के प्रमुख केंद्रों में स्थापित करता है

■ यह रैंकिंग प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक, शोधकर्ता और कर्मचारी की सामूहिक मेहनत और समर्पण का परिणाम है : कुलपति प्रो. आनंद भालेराव

शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थानों की विशिष्ट श्रेणी में शामिल हो गया है और यह नए विकास, अवसरों और आकांक्षाओं के अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आनंद भालेराव ने कहा कि यह रैंकिंग प्रत्येक विद्यार्थी, शिक्षक, शोधकर्ता और कर्मचारी की सामूहिक मेहनत और समर्पण का परिणाम है। शीर्ष 1०0 विश्वविद्यालयों में स्थान बनाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, यह तो नियति का अद्भुत उपहार है। विश्वविद्यालय परिसर में इस उपलब्धि का जश्न बड़े उत्साह और गर्व के साथ मनाया गया। पूरे कैम्पस में खुशी की लहर दौड़ गई और वातावरण आतिशबाजी, तालियों और हार्पोल्लास से गुंज उठा।

राशिफल मंगलवार 9 सितम्बर, 2025



पंडित अनिल शर्मा

आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, डत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सायं 6:07 तक, गंड योग रात्रि 11:59 तक, तैतिल करण प्रातः 7:51 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मीन, मंगल-कन्या, बुध-सिंह, गुरू-मिथुन, शुक्र-कर्क, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धियोग और राजयोग सूर्योदय से सायं 6:07 तक है। आज पंचक, ग्रहण वैध है।

श्रेष्ठ चौघड़िया चर 9:19 से 1०:52 तक, लाभ-अमृत 1०:52 से 1:57 तक, शुभ 3:50 से 5:03 तक। राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:13, सूर्यास्त 6:35

 मेघ घर-गृहस्थी के खर्चों कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।	 सिंह चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियाँ अभी बनी रहेंगी।	 धनु घर-परिवार में वाद-विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है।
 वृष आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे।	 कन्या परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 मकर परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवर्जनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं।
 मिथुन व्यावसायिक कार्यों के प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 तुला व्यावसायिक कार्यों से संबंधित विवादों से राहत मिल सकती है। अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 कुंभ आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लगेंगे। स्वास्थ्य संबंधित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदौड़ रहेगी। घर-परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।
 कर्क व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिल सकती है। व्यावसायिक याताा के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।	 वृश्चिक व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक सफलता से आत्मविश्वास बढ़ेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।	 मीन मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मेडिकल व्यापारी के घर हुई एक करोड़ की लूट की वारदात का खुलासा, चार गिरफ्तार

मेडिकल व्यापारी की दुकान पर काम कर चुके सेल्समैन ने ही रची थी लूट की साजिश

बाड़मेर, (नि.सं.)। जिले के सरहदी गडरा रोड कस्बे में गत तीन सितंबर की मध्यरात्रि में मेडिकल व्यापारी के घर हुई करोड़ों की लूट का बाड़मेर पुलिस ने 72 घंटों में पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को बापर्दा गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी अलग-अलग मेडिकल दुकानों पर काम करते है और वारदात का मास्टरमाइंड आरोपी व्यापारी की दुकान पर काम कर चुका है। ऐसे में उसे व्यापारी की पूरी जानकारी थी और अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की तनख्वाह अधिक नहीं थी, इसलिए अपने मौज और शोक को पूरा करने के लिए इन्होंने यह लूट की। पुलिस ने 72 घंटो के अंदर वारदात का खुलासा किया। मामले में आरोपियों से माल की बरामदगी और अन्य आरोपियों की दस्तयाबी को लेकर जांच जारी है।

पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि गत 4 सितंबर की रात्रि में करीब 1.30 बजे गडरा रोड़ कस्बे में मेडिकल व्यापारी उत्तमचंद पुत्र हाथीराम माहेश्वरी के घर की छत के रास्ते चार नकाबपोश लुटेरों द्वारा घर में प्रवेश कर परिव्दाी उत्तमचंद व उसके परिवार के साथ मारपीट कर बंधक बनाकर 40-45 तोला सोना, 50-

- सभी आरोपी बाड़मेर के अलग-अलग मेडिकल दुकानों पर काम करते हैं, वारदात का मास्टरमाइंड व्यापारी की दुकान पर काम कर चुका है**

- मेडिकल व्यापारी उत्तमचंद पुत्र हाथीराम माहेश्वरी के घर से लुटेरे 40-45 तोला सोना, 50-60 किलो चांदी व 1.25 लाख रुपए नकद लूटकर ले गए थे**

60 किलो चांदी व 1.25 लाख रुपए नकद लूटकर ले गए। जिले में यह लूट की सबसे बड़ी वारदात थी और इस घटना के बाद क्षेत्र में भय व्याप्त हो गया। लूट की घटना को लेकर स्थानीय ग्रामीणों सहित मेडिकल एसोसिएशन ने भी आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपे थे। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा व अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस के नेतृत्व एवं अतिरिक्त पुलिस अधिकारी, महिला अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ नितेश आर्य व रामसर वृताधिकारी मानाराम गर्ग के सुपरविजन में विशेष टीमों व स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर आवश्यक निर्देश दिए जिस पर पुलिस टीमों ने मामले में गहन अनुसंधान करते

हुए घटनास्थल व अपराधियों के आने जाने के रास्ते, पेट्रोल पंप, टोल नाकों के करीब 100 से ज्यादा कैमरों और 80 किलोमीटर में आने वाले बाड़मेर, जैसलमेर व जालोर के क्षेत्र में समस्त संभावित रास्तों के फुटेज का विश्लेषण कर आरोपियों की पहचान व भागने के रास्तों का पता लगाने का प्रयास किया। गडरा रोड़ कस्बे में पिछले दिनों आने जाने वाले लोगों की गोपनीय सूचना ली गई और पीड़ित व्यापारी के दुकान व घर में पिछले 15 सालों तक काम करने वाले घरेलू नौकर और सेल्समैन की जानकारी जुटाकर उन पर विशेष निगरानी रखी गई।

पुलिस द्वारा मामले में किए गए अनुसंधान और उच्च अधिकारियों द्वारा घटनाक्रम को बारीकी से समझने पर शक की सुई स्थानीय किसी नौसिखिए बदमाश व पीड़ित परिवार के किसी पहचान वाले पर गई। इस दौरान परिव्दाी की गडरा रोड़ स्थित मेडिकल

दुकान पर कुछ साल पहले काम कर चुके युवक व उसके फार्मा सेल्समैन मित्रों की असामान्य गतिविधियों व डाटा पैटर्न का बारीकी से विश्लेषण किया गया तो उक्त कार युवक संदेह के घेरे में आ गए जिस पर इन युवकों को पुलिस द्वारा सर्विलांस पर रखा गया। पुलिस ने तीन दिन तक अथक प्रयास कर आरोपियों को ट्रैसआउट कर गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि वारदात में शामिल मुख्य आरोपी पहले परिव्दाी उत्तमचंद की मेडिकल दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करता था। ऐसे में उसे परिव्दाी के घर दुकान की पूरी जानकारी थी। वारदात में शामिल सभी आरोपी बाड़मेर में अलग-अलग मेडिकल की दुकानों पर सेल्समैन की नौकरी करते है तथा सभी अलग अलग गांव के निवासी है। चारों आरोपी मेडिकल की दुकान पर नौकरी करने के दौरान आपस में परिचित हुए थे।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गडरा निवासी लुटेरों ने अपने पुराना सेठ आयु में अधिक होने, घर पर कम सदस्य रहने तथा ज्यादा माल मिलने की जानकारी होने पर अपने अन्य 3 दोस्तों के साथ मिलकर कई दिनों तक इस लूट की योजना बनाते हुए परिव्दाी के पुत्र के गडरा से बाहर जाने का इंतजार किया, जब इन्हें पता चला कि

परिव्दाी का पुत्र आज गडरा से बाहर है, घर पर केवल परिव्दाी व उसकी वृद्ध पत्नी तथा उसकी पुत्री तथा दूधमुही नालिन होने का मौका देखकर घटना को अंजाम देने का फैसला किया। इन चारों अपराधियों द्वारा अलग-अलग साधनों से 3 तारीख की शाम गडरा पहुंच परिव्दाी के मकान की रैकी करना प्रारम्भ की तथा मध्य रात्रि में कस्बा में लगे सीसीटीवी कैमरों से बचाव करते हुए परिव्दाी के पडौसी मकान की छत पर चढ़कर सीढ़ियों के रास्ते परिव्दाी के घर में प्रवेश किया तथा परिव्दाी व उसके परिवार को एडेसिव टेप से हाथ व मुंह बांधकर उक्त वारदात को अंजाम दिया। वारदात के पश्चात चारों लुटेरों परिव्दाी की पुत्री का मोबाइल पास स्थित रेलवे ट्रैक की लुटेरे प्रातः नियमित दिग्दर्श्यों अनुसार अपनी-अपनी मेडिकल की दुकान पर पहुंचकर कार्य करने लगे जिससे लोगों में किसी प्रकार का शक न होा। उक्त चारों अपराधियों के विरूद्ध पूर्व में कोई प्रकरण दर्ज होना नहीं पाया गया है।

परीक्षा केन्द्र पर कुछ सेकण्ड लेट पहुंची युवती, नहीं मिली परीक्षा की अनुमति

टोंक, (निस्ं)। आरपीएससी की वरिष्ठ अस्थापक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन सोमवार को पहली पारी की परीक्षा 29 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। पहली पारी में रजिस्टर्ड 9960 अभ्यर्थियों में से 7675 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। वहीं रविवार को मालपुरा क्षेत्र की एक युवती 10-15 सेकेंड लेट होने से पर परीक्षा सेंटर सेंट सोलजर स्कूल के बाहर गेट पर ही बैठकर खूब देर तक रोई, उसने रोते हुए गेट पर हाथ मार कर काफी देर तक गेट खोलने की गुहार लगाई, लेकिन परीक्षा के नियमों के आगे

- मालपुरा क्षेत्र की एक युवती 10-15 सेकेंड लेट होने से पर परीक्षा सेंटर के बाहर गेट पर ही बैठकर खूब देर तक रोई**

- रोते हुए गेट पर हाथ मार कर काफी देर तक गेट खोलने की गुहार लगाई, लेकिन परीक्षा के नियमों के आगे सब बेबस नजर आए**

सब बेबस नजर आए। गेट नहीं खुलने पर लोगों ने उसे समझाकर घर के लिए रवाना कर दिया। ऐसे ही इमानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल टोंक पर भी एक

दो मिनट लेट आए चार अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित हो गए।

अति. जिला कलेक्टर रामरतन सौकरिया ने बताया कि रविवार को

पहली पारी सुबह दस बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पारी दोपहर बाद तीन बजे से शाम साढ़े 5 बजे तक होगी। एक घंटे पहले परीक्षा सेंटर पर प्रवेश बंद कर दिया जाएगा, पुलिस समेत अन्य की माकूल व्यवस्था की गई है। 12 सितंबर तक चलने वाली सेकेंड ग्रेड भर्ती इस परीक्षा के लिए जिले में 72 हजार से अधिक अभ्यर्थी रजिस्टर्ड है। कड़ी चौकंग के बाद परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से सेंटर पर दो घंटे पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है।

फर्जी सिम बेचने वाला दुकानदार गिरफ्तार

भवानीमंडी, (निर्सं)। पुलिस ने साइबर अपराध में लिप्त एयरटेल सिम विक्रेता के खिलाफ साइबर सैल झालावाड़ व भवानीमंडी पुलिस से संयुक्त कारवाई करते हुए 10 एयरटेल कंपनी की 5 जी सिम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी ग्राहकों के जानकारी के बिना उतापी आईडी से केवाईसी के नियमों का उल्लंघन कर एक से अधिक बार केवाईसी कर एक से अधिक फर्जी सीमें षडयंत्रपूर्वक धोखाधड़ी से एवं कुतरांचित पकड़ जारी करता था। थानाधिकारी रमेशचंद मीणा ने बताया कि सिम विक्रेता ग्राहकों की जानकारी के बिना उनकी आईडी से सिम जारी करता है।

बैंक में चोरी का प्रयास विफल

उदयपुर, (निर्सं)। जिलें में देर रात थाने से महज 150 मीटर दूरी पर चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक की दीवार तोड़कर चोरी की कोशिश की। इस दौरान आवाज सुनकर आसपास के लोग जाग गए। बाहर आकर देखने पर चोर भाग निकले। चोरों ने बैंक की साइड की दीवार पर नोचे की तरफ करीब दो फीट का छेद कर दिया था। घटना कोटडा थाना क्षेत्र में बीती रात करीब ढाई बजे की है। दीवार तोड़े जाने की आवाज सुनकर आसपास लोग जाग गए। लोगों ने बाहर आकर देखा तो दो युवक दिखाई दिए। इसके बाद बदमाश तुरंत मौके से फरार हो गए। लोगों का कहना है कि कुछ देर से दीवार को तोड़े जाने की आवाज लगातार आ रही थी। कोई घटना का अंदेश होने से वे घर से बाहर आए तब वारदात का पता लगा।

उदयपुर-झाड़ोल हाइवे पर लैंडस्लाइड होने से जाम लगा

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर में सोमवार सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और हल्की बूंदाबांदी हुई। ठंडी हवाएं चलने के साथ ही मौसम में ठंडक घुल गई। इधर मौसम विभाग ने सोमवार को भी येलो अलर्ट के साथ बारिश की चेतावनी दी। वहीं उदयपुर-झाड़ोल इंटर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 ई पर लैंडस्लाइड होने से जाम लग गया था जो पूरी तरह से दोपहर में जाकर खुला। हाइवे पर उन्दवेला में लैंडस्लाइड हुई।

पहाड़ियों से बड़े-बड़े पत्थर हाइवे पर गिर गए जिससे दोनों तरफ से यातायात बाधित हो गया। इससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहां पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर रास्ता साफ करने का काम शुरू किया। सूचना पर झाड़ोल थाने से पुलिस भी मौके पर पहुंची। दोपहर बाद पूरी तरह से मार्ग खुल गया था। रविवार रात को तेज बहाव के चपेट में आये युवक का शव सोमवार को मिला। वहीं सोमवार को एक वृद्ध तेज बहाव में बह गया।

उदयपुर में रविवार रात करीब 11 बजे भूपालपुरा थाना क्षेत्र के अलीपुरा में स्थित शहीद भगत सिंह ब्रिज के वहां पानी में बहे एक युवक का सोमवार तड़के तक पता नहीं चला। सिविल डिफेंस की टीम ने वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इसके बाद सोमवार सुबह वापस उसे पर्रिजनों और अन्य ने खोजना शुरू किया तो जहां वह गिरा उससे आधा किलोमीटर दूर उसका

- पहाड़ियों से बड़े-बड़े पत्थर हाइवे पर गिर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया**

- अलीपुरा से बहे युवक का शव मिला, सायरा के पास नदी में बहा वृद्ध**

शव मिला। मृतक की शिनाख्त शेख (26) के रूप में हुई है। वहीं उदयपुर के सायरा क्षेत्र में तिरोल के बोरमचा पुलिया से एक वृद्ध पानी में बह गया। पुलिया पार करते 60 वर्षीय रोहिडा गांव का रहने वाला जालूराम गमेती तेज पानी के बहाव में बह गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वृद्ध बह रहा था। सूचना मिलने पर गोगुंदा उपखण्ड अधिकारी शुष्म भैसारे, सायरा तहसीलदार सुरेश मेहता, थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत मौके पर पहुंचे। तहसीलदार सुरेश मेहता ने बताया कि सुबह करीब दस बजे की घटना है। ग्रामीणों ने उसे जाने से मना किया लेकिन वह बनास नदी की पुलिया पर गया और तेज पानी के साथ बह गया। उन्होंने बताया कि उसने तैरते हुए बचने की काफी कोशिश की लेकिन पानी का वेग तेज था और वह बह गया। उदयपुर से सिविल डिफेंस की टीम को बुलाया गया लेकिन इससे पहले करीब 400 मीटर की दूरी पर उसका शव नदी किनारे मिला।

उदयपुर जिले के कैचमेंट क्षेत्र में हुई बारिश से जलाशयों में लगातार पानी की आवक जारी है। आगड़ नदी में

लगातार पानी बढ़ने से किसानों की फसल चौपट हो गई है। आयड नदी के उफान पर आने के बाद उदयसागर के आस-पास के गांवों में तबाही मची हुई है। उदयसागर की पूर्ण भराव क्षमता 24 फीट है और यह शनिवार देर रात करीब 28 फीट तक भर गया। सोमवार को भी उदयसागर का गेज 27.50 फीट पर था। उदयसागर के बैक वाटर से प्रभावित गांवों में हजारों बीघा खेतों में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और सब्जियां उदयसागर के बैकवाटर में दफन हो चुकी हैं। पशुओं को खिलाने वाला चारा भी पानी से बर्बाद हो चुका है। कानपुर के पूर्व उप सरपंच मदनलाल डांगी ने बताया कि आयड नदी के दोनों छोर पर स्थित गांवों के किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं। प्रभावित गांवों में कानपुर, नदी वाला खेडा, भोड़यों की पंचोली, खरबडिया, मटून और लकडवास शामिल हैं। डांगी ने बताया कि किसानों की फसल, सब्जियां और पशुओं का हरा चारा पूरी तरह से तबाह हो गया है। उन्होंने सरकार से तुरंत प्रभाव से मुआवजा जारी करने और सूखा चारा उपलब्ध कराने की मांग की है।

जुआ खेलने वाले सात जुआरी गिरफ्तार



पुलिस ने जुआ खेलने के मामले में सात जनों को गिरफ्तार किया।

ब्यावर, (निर्सं)। जिला पुलिस अधीक्षक रतन सिंह आईपीएस के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र शर्मा, आरपीएस एवं वृताधिकारी राजेश कसाना, आरपीएस के निकट सुपरविजन में थानाधिकारी सदर, गजराज पु.नि. मय टीम द्वारा थाना क्षेत्र के रामगढ़ झूठा के काकड़ की झाड़ियों

- रामगढ़ झूठा के जंगल में जुआ खेलते वाले जुआरियों के विरूद्ध कार्रवाई, जुआ राशि जब्त की**

निवासी मेवाड़ी गेट सब्जी मण्डी रोड, सूर्यप्रकाश उर्फ सूरज पुत्र द्वाराकाप्रसाद दाधिच कॉलोनी मसुदा रोड, सुरेश सोनी उर्फ कालुगाम पुत्र पुछराज सोनी निवासी अस्पताल रोड मारवाड जंक्शन, कैलाश सिंह पुत्र भरमा सिंह रावत निवासी बिजयनगर रोड सेदरिया जेल के सामने, कालु पुत्र जमाल शेख निवासी बिजयनगर रोड सेदरिया, दीपु पुत्र मनोहरलाल खटीक निवासी लोकाशाह नगर सब्जी मंण्डी के सामने आदि को गिरफ्तार किया।

जुआ खेलते सात गिरफ्तार

टोंक, (निर्सं)। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के निर्देशन में उनीयारा थानाधिकारी कप्तान सिंह के

नेतृत्व में गठित टीम ने कस्बा उनीयारा में सवाई माधोपुर रोड बंसल पेट्रोल पम्प के पास स्थित एचएससी की दुकानों के पास बन्बूलों की आड़ में दो अलग-अलग गुटों को जुआ खेलते हुये सात आरोपियों को गिरफ्तार कर रुपये कब्जे से जुआ राशि 71 हजार रुपये जब्त की।

थाना टीम ने जुआ खेलने की मिली सूचना पर कार्रवाई कर कई स्थानों पर दबिश देकर एक स्थान से चार आरोपी जिनके कब्जे से 43 हजार रुपये की राशि तथा द्वितीय टीम द्वारा तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 28 हजार रुपये जब्त किये गये। इस कार्रवाई में जितेन्द्र पुत्र मांगीलाल बैरवा, रामजीलाल पुत्र तुलसीराम, बन्ना खां पुत्र फकीर मोहम्मद, विजय कुमार पुत्र प्रकाश, विकास कुमार उर्फ बिडु पुत्र रतन लाल, ओमप्रकाश पुत्र आशाराम व रोहितारा पुत्र काशीराम जाट समस्त निवासी थाना बनेठा जिला टोंक को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ बीएएस व आरपीजीओ में प्रकरण दर्ज किया गया, जिन्हें न्यायालय एसीजेएम उनीयारा में पेश किया गया।

चौरड़ी कृषि पर्यवेक्षक से चार लोगों ने मारपीट की, अस्पताल में भर्ती कराया

दौसा, (निर्सं)। सैथल थानानर्गत बासडी चौराहा पर रविवार रात्रि को चार लोगों ने चौरड़ी कृषि पर्यवेक्षक राकेश कुमार मीणा के साथ जमकर मारपीट कर दी, जिसके चलते कृषि पर्यवेक्षक गंभीर रुप से घायल हो गये, जिन्हे स्थानीय लोगों की मदद से उपचार के लिए राजकीय जिला चिकित्सालय भर्ती कराया है। इधर उक्त घटनायें से गुस्साये कृषि अधिकारी एवं दर्जनों कृषि पर्यवेक्षक सैथल थाना पहुंचे तथा मारपीट करने वालो को तत्काल गिरफ्तार किये जाने की मांग की। उपर मामला तेजी से बढ़ने की आशंका के चलते सैथल पुलिस ने मारपीट के आरोप में एक जने को गिरफ्तार कर लिया है।

सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा अशोक कुमार मीना ने बताया कि रविवार को क्षेत्र में फसलों में हुए खराबा का सर्वे करने के लिए कृषि पर्यवेक्षक चौरड़ी राकेश कुमार मीना अपने कार्य क्षेत्र में आए हुए थे। राजकाय करने के बाद सूचना देने के लिए सहायक कृषि अधिकारी मुख्यालय सैथल जा रहे थे। रास्ते में बासडी चौराहा पर दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार लोगों ने उन्हें रास्ते में रोककर उनके साथ अपद्र व्यवहार किया एवं मारपीट की और उनके पास जो राजकीय दस्तावेज थे उन्हें



सैथल थाना के बाहर कृषि पर्यवेक्षकों ने प्रदर्शन किया।

फाड़ दिया। मौके पर उपस्थित लोगों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें इन लोगों से बचाया, उसके बाद सहायक कृषि अधिकारी सैथल घासीराम मीणा एवं कृषि पर्यवेक्षक चौरड़ी राकेश कुमार मीणा पुलिस थाना सैथल पहुंचे एवं उक्त सभी चारों आरोपियों के खिलाफ मारपीट एवं राजकाय में बाधा के संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

दूरभाष पर सहायक कृषि अधिकारी सैथल घासीराम मीणा ने इस

घटना की सूचना सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा अशोक कुमार मीणा एवं संयुक्त निरेशक कृषि (विस्तार) दौसा रामराज मीना को दी। सैथल पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद देर रात्रि राकेश कुमार मीना कृषि पर्यवेक्षक चौरड़ी को राजकीय जिला चिकित्सालय दौसा में आपातकालीन वार्ड में लेकर पहुंचे एवं उनका इलाज करवाया गया। इस घटना से जिले के कृषि विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। सोमवार को कृषि विभाग

के अधिकारी एवं कर्मचारी सैथल पुलिस थाना पहुंचे एवं आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई कृषि विभाग के अधिकारियों की मांग है कि जल्द से जल्द अन्य तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए, यदि 2 दिन में सभी आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं की गई तो जिले के कृषि विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा जिला कलक्ट्रेट पर अर्निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान सहायक

- कृषि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सैथल पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया**
- मामला तेजी से बढ़ने की आशंका के चलते पुलिस ने एक जने को गिरफ्तार किया**
- क्षेत्र में फसलों में हुए खराबा का सर्वे करने के लिए कृषि पर्यवेक्षक चौरड़ी राकेश कुमार मीना अपने कार्य क्षेत्र में आए हुए थे**

निदेशक कृषि (विस्तार) दौसा अशोक कुमार मीणा, सहायक कृषि अधिकारी घासीराम मीणा, घासीराल मीणा, ओमप्रकाश बैरवा, कृषि पर्यवेक्षक वीणा मीणा, अनीता मीणा, चमेलाबाई मीणा, राकेश कुमार मीणा एवं उनके परिजन एवं क्षेत्र के किसान मौजूद रहे।

अफीम से भरा बैग फेंककर भागा एक और आरोपी गिरफ्तार

एनडीपीएस के मामले में लंबे समय से फरार ईनामी आरोपी जगदीश उर्फ जेडी को गिरफ्तार किया

बांसवाड़ा, (निर्सं)। पुलिस उप अधीक्षक गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में पुलिस दल ने 10 मई 2023 को अफीम धरा बैग फेंककर भागने के मामले में ईनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है।

जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के सुपरविजन में बांसवाड़ा पुलिस व जोधपुर साइक्लोनर टीम ने एनडीपीएस के मामले में लंबे समय से फरार ईनामी आरोपी जगदीश उर्फ जेडी पुत्र मांगीलाल खिलेरी विश्नोई निवासी भारताशियों की ढाणी, एकल खोरी, थाना ओसिया जिला जोधपुर को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार 10 मई 2023 को तत्कालीन थानाधिकारी कोतवाली रतन सिंह ने मय जाने के नाकाबंदी के दौरान नकाबंदी तोड़कर भागी कार का पीछा किया तो आरोपियों ने चलती कार से बैग फेंक दिया और कार को लड्डा हॉस्पिटल के पास छोड़कर भाग गये थे। बैग में 16 किलो 2.5 ग्राम अवैध अफीम होने से अफीम व कार जब्त की गयी थी। अनुसंधान

- आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जोधपुर, फलोदी आदि स्थानों पर गयी एवं स्थानीय पुलिस को अवगत कराया था**

के दौरान आरोपी भरतदान उर्फ भरत चारण निवासी नोखड़ा चारणान, जिला फालौदी को गिरफ्तार किया था। भरतदान ने बताया कि उसने यह अफीम राहुल लोहार एवं पुश्करदास बैरागी से ली थी जिससे किसी मिलने वाले व्यक्ति से एकत्रित कर रखी थी। इसके पैसे भरतदान व जगदीश उर्फ जेडी ने दिये थे।

इस अफीम में से 1 किलो लक्ष्मण पुत्र बाबुराम विश्नोई निवासी जेसला व 2 किलो अशोक पुत्र परतापाराम निवासी जेसला को देनी थी। 1 किलो रामस्वरूप निवासी जेसला और 3 किलो सुभाष विश्नोई निवासी नोखड़ा को देनी थी वहीं शेष 9 किलो अफीम

जगदीश उर्फ जेडी को अपने पास रखनी थी। अभियुक्त भरतदान व पुष्करदास टाटा हेरियर तथा अशोक व राहुल लोहार क्रेटा गाड़ी में थे। बांसवाड़ा पुलिस ने अशोक की क्रेटा कार रोकने का ईशारा किया था जिस पर अशोक कार लेकर भाग निकला और उसके पीछे-पीछे इन लोगों की गाड़ी भी निकल गयी।

अभियुक्त भरतदान उर्फ भरत चारण को बांसवाड़ा पुलिस ने स्थानीय पुलिस की सहायता से गिरफ्तार किया। शेष आरोपी फरार थे जिन पर जिला पुलिस अधीक्षक ने बीस-बीस हजार रूपये के ईनाम की घोषणा की थी। इसके पश्चात् आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम जोधपुर, फलोदी आदि स्थानों पर गयी एवं स्थानीय पुलिस को अवगत कराया। स्थानीय पुलिस व बांसवाड़ा पुलिस ने आरोपी के निवास पर कई बार दबिश दी व दबाव भी बनाया था। जिसके चलते आरोपी जगदीश उर्फ जेडी विश्नोई को जोधपुर से गिरफ्तार किया गया।

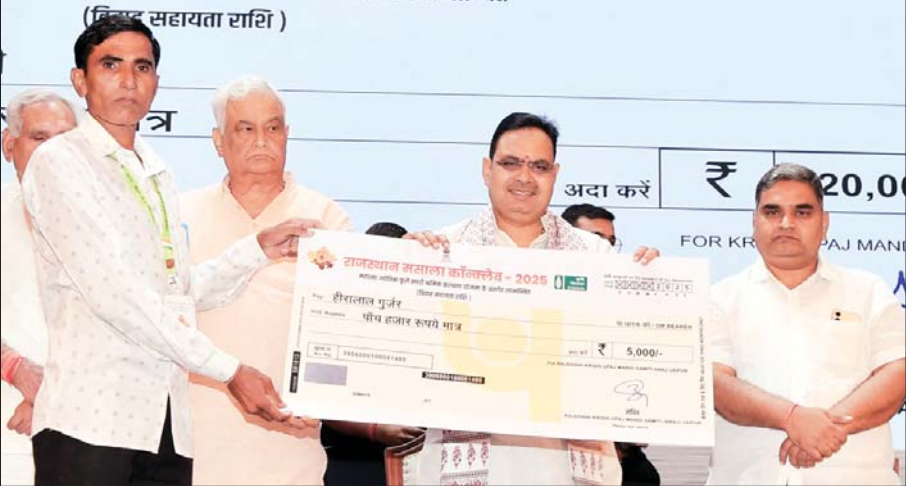
‘हर साल होगा राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव का आयोजन’

मुख्यमंत्री ने मसालों की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग व निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए यह घोषणा की

जयपुर, 8 सितंबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित “राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव-2025” का भव्य शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि अब यह आयोजन हर वर्ष किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मसालों के क्षेत्र में

मुख्यमंत्री भजनलाल ने जोधपुर के आंगणवा में तथा टोंक के सोहेला में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर्स का वर्चअल लोकार्पण किया।

राजस्थान की समृद्ध परंपरा और उत्पादन क्षमताएं इसे देश और दुनिया में विशिष्ट स्थान दिलाती हैं। यह कॉन्क्लेव किसानों, उत्पादकों और व्यापारियों को एक वैश्विक मंच उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि राजस्थान देश में जीरा उत्पादन में प्रथम, मेथी और सौंफ में द्वितीय तथा धनिया और अजवाइन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि मसालों के क्षेत्र



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के बिड़ला सभागार में “राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव-2025” का शुभारंभ किया और एकपीओ पंजीयन प्रमाण पत्र, श्रम सम्मान कार्ड, मसालों से जुड़ी योजनाओं के फोल्डर और कृषि विपणन योजनाओं के चेक भी वितरित किए गए।

को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात के क्षेत्रों में सरकार द्वारा ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जोधपुर के आंगणवा और टोंक के सोहेला में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर्स का वर्चअल लोकार्पण किया। इसी के साथ टोंक जिले के सोनवा में फूड पार्क का भी

उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज-स्पाइस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया और एकपीओ पंजीयन प्रमाण पत्र, श्रम सम्मान कार्ड, मसालों से जुड़ी योजनाओं के फोल्डर और कृषि विपणन योजनाओं के चेक भी वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि खाद और बीज की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इस आयोजन में सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक, शासन सचिव कृषि राजन विशाल सहित बड़ी संख्या में कृषक, मसाला व्यापारी और कृषि विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

“आधार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) सुप्रीम कोर्ट बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। राज्य में विपक्ष, जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल शामिल हैं और जो महागठबंधन का हिस्सा हैं, ने तर्क दिया है कि यह पुनरीक्षण लाखों ऐसे पुरुषों और महिलाओं को मताधिकार से वंचित करने की साजिश है, जो परंपरागत रूप से उनके पक्ष में मतदान करते हैं। कांग्रेस ने यहाँ तक आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर वोटर लिस्ट में धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि, चुनाव आयोग ने जोर देकर कहा है कि उसका गहन पुनरीक्षण कानूनी और संवैधानिक दायरे में है और मतदाता दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की गई है।

संघ के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले कोर कमेटी के कुछ सदस्यों के साथ यहीं रुके हुए हैं। सोमवार दोपहर दो बजे के करीब होसबोले की तबीयत बिगड़ गई। तत्काल उनको एम्स में भर्ती करवाया गया। सूचना पर बाड़मेर के पूर्व सांसद मानवेन्द्र सिंह जसोल, आरएसएस जोधपुर प्रांत के विद्यानंद भाईसाहब, कलेक्टर गौरव अग्रवाल और कमिश्नर ओमप्रकाश पासवान भी एम्स पहुंचे। होसबोले आरएसएस में मोहन भागवत के बाद दूसरे सबसे बड़े पदाधिकारी हैं।

जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) बीआरएस (चार सांसद) और बीजद (सात सांसद) का रुख अभी स्पष्ट नहीं है। बीआरएस पार्टी प्रमुख केशीआर की बेटी के. कविता के इस्तीफे और भाजपा व कांग्रेस दोनों के खिलाफ आक्रामक रुख के कारण बी आर एस में आंतरिक उथल-पुथल चल रही है, इसलिए उसके चुनाव से दूर रहने की संभावना है। इसके अलावा, बीआरएस की नजर जुबली हिल्स विधानसभा सीट के उपचुनाव पर भी है, जहाँ मुस्लिम वोट अहम माने जाते हैं। यह सीट मगन्ती गोपीनाथ ने 2018 और 2023 में बी.आर.एस. के लिए जीती थी, गोपीनाथ की जून में मृत्यु हो गई। बीजू जनता दल (बीजद) से समर्थन की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन उसने अब तक औपचारिक घोषणा नहीं की है। माना जा रहा है कि वह अब भी असमंजस में है, क्योंकि पिछले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उसे कड़ी टक्कर दी थी। इसके बावजूद, बीआरएस और बीजद का समर्थन नहीं मिलने पर भी एनडीए के पास 436 वोट होंगे और यह संख्या और भी बढ़ सकती है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी इस चुनाव में एक दिलचस्प पहलू हैं। पिछले साल उनका अपनी ही पार्टी से रिश्ता उस समय टूट गया था, जब उन्होंने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी पर शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया था। तब से उनके आप को छोड़ देने तथा भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगाई जाती रहीं, लेकिन उन्होंने न तो अपने पद से इस्तीफा दिया और न ही पार्टी बदली। इससे चुनाव और रोचक हो गया है। इसके अलावा, लोकसभा के

- पर, बी.आर.एस. व बी.जे.डी. के समर्थन के बिना भी एन.डी.ए. को 436 वोट मिलने की संभावना।
- आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालिवाल भी केजरीवाल के खिलाफ हैं, जब से केजरीवाल के नुमाइन्दे ने उस पर राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिलवाने का भारी दबाव डाला था।
- परन्तु, अगर ये सभी पार्टियां, इण्डिया गठबंधन के पक्ष में मतदान करती भी हैं, तो भी इण्डिया गठबंधन को जीतने के लिए सत्तर वोट कम पड़ेंगे।
- इस सत्य से विपक्ष भी अनभिज्ञ नहीं, पर विपक्ष का मानना है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में अगर उनका प्रदर्शन ठीक रहे, और चुनाव में विपक्ष की एकता बरकरार रही, तो इस माहौल का लाभ इस वर्ष व अगले वर्ष, बिहार, बंगाल व तमिनलाडु के विधानसभा चुनाव में मिलेगा।

सात निर्दलीय सांसदों के बारे में भी अनिश्चितता की स्थिति है। इसी तरह अकाली दल और मिजोरम की जेडपीएम का भी रुख साफ़ नहीं है, जिनमें से प्रत्येक के एक-एक सांसद हैं। अगर ये सभी वोट राधाकृष्णन के पक्ष में पड़ते हैं, तो भाजपा उम्मीदवार 458 वोट तक पहुँच सकते हैं। यह संख्या तीन साल पहले धनखड़ को मिले 528 वोटों से काफी कम होगी, लेकिन जीत के लिए पर्याप्त रहेगी। विपक्षी खेमे में, कांग्रेस नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों सदनों को मिलाकर, कागज़ पर विपक्ष के पास 324 वोट हैं। इस बार चुनाव 2022 की तुलना में कड़ा दिख रहा है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बेहतरे प्रदर्शन के चलते विपक्ष के पास ज्यादा सांसद हैं।

लेकिन फिर भी उनकी जीत की संभावना लगभग “नहीं” के बराबर है। अगर विपक्ष के सारे सांसद वोट डालें और सभी न्यायमूर्ति रेड्डी के पक्ष में वोट दें, तब भी उन्हें 100 से 135 वोट कम ही मिल पायेंगे। यह स्थिति तब भी नहीं बदलेगी, यदि बीआरएस, बीजद, स्वाति मालीवाल, सभी निर्दलीय, एक-सांसद वाली पार्टियाँ और यहाँ तक कि वाईएसआर कांग्रेस भी विपक्ष के साथ चली जाएं। तब भी इंडिया ब्लॉक के करीब 70 वोट कम रह जाएंगे। स्थिति और भी कठिन इसलिए हो गई है, क्योंकि एनडीए के सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि उन्हें सिर्फ़ राज्यसभा में ही कम से कम 150 क्रॉस वोट की उम्मीद है। इंडिया ब्लॉक पहले ही मान चुका है कि वह यह चुनाव जीतने की उम्मीद नहीं कर रहा। सूत्रों का कहना है कि यह चुनाव कराना विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है- ताकि विपक्ष पिछली बार के उपराष्ट्रपति चुनाव की तुलना में अपनी अतिरिक्त ताकत दिखा सके और आने वाले विधानसभा चुनावों (जिनमें बिहार, बंगाल और तमिलनाडु शामिल हैं) से पहले गति पकड़ सके।

‘वो बात सारे फसाने में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) नकल करके पास हुए अभ्यर्थियों से अलग करना असंभव है। इस रोचक मामले को सुनवाई के दौरान ही ना तो राज्य सरकार और ना ही प्रतिवादी पक्ष, जो परीक्षा को रद्द करने के पक्ष में नहीं था, ने याचिकाकर्ता पर अंगुली उठाई और कहा कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई एसआईटी रिपोर्ट वास्तविक नहीं है। उल्लेखनीय है कि राफेल खरीद के मामले के दौरान भी यशवंत सिन्हा और हिंदू अखबार के संपादक व चेयरमैन रह चुके एन. राम पर आरोप लगे थे कि, उन्होंने राफेल की खरीद के संबंध में दस्तावेज जो अदालत में प्रस्तुत किए थे, वह डिफेंस मिनिस्ट्री से चुराए हैं और इन दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से भारत की अखंडता व सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा यह भी जिरह की गई थी कि, राफेल की खरीद, उसके दाम और इसकी विशिष्टता विभागीय

गोपनीय दस्तावेज हैं, जिसकी चोरी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि, दस्तावेज जहाँ से भी लाए गए हों, परंतु जनहित में इन्हें अदालत में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि, एस.आई.भर्ती-2021 में राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत जिस एसआईटी रिपोर्ट पर इतना बवाल खंडपीठ खड़ा कर रही है। उस रिपोर्ट को अब तक ना तो कभी एस.ओ.जी. ने झूठा बताया और ना ही राज्य सरकार ने इस पर कोई सवाल खड़े किए। इनके अलावा प्रतिवादी पक्ष ने भी कभी इसे चुनौती नहीं दी तो आखिर अब खंडपीठ इसकी वास्तविकता का प्रश्न क्यों किस के आधार पर उठा रही है? इस मामले को जानने वाले सूत्रों का कहना है कि, अगर इस मामले की सुनवाई अगली तारीख 8 अक्टूबर को नहीं हुई और स्टे जारी रहा तो इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष) है, “हैरानी की बात यह थी कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा कोई झंडा-बैनर या पहचान नहीं दिखा।” काठमांडू की गंभीर स्थिति को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आनन-फानन में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। संकट की समीक्षा के लिये संध्या को मंत्रिपरिषद और सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। काठमांडू के कई हिस्सों में झड़पों के बाद दिनभर का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार,

प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया है क्योंकि प्रदर्शन हिंसक हो गया था। स्थिति तब और बिगड़ गई, जब प्रदर्शनकारियों ने प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमाएं तोड़ दी और संसद भवन के परिसर में घुस गए। पुलिस ने जवाब में वॉटर कैनन, आंसू गैस का प्रयोग किया और फायरिंग की, जिससे कई लोग घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कम से कम 42 लोग घायल हुए हैं। सरकार ने कहा कि जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक किया गया है, वे सरकार के साथ पंजीकरण

नहीं करवा रहे थे। इन प्लेटफॉर्मों के दुरुपयोग पर नाराजगी जताते हुये सरकार ने कहा कि फर्जी आईडी का उपयोग करके नफरत फैलाना, अफवाहें उड़ाना, साइबर क्राइम करना और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना इन प्लेटफॉर्मों के ज़रिए किया जा रहा था, वास्तविकता यह है कि देश की 3 करोड़ आबादी का 90 प्रतिशत हिस्सा इंटरनेट का उपयोग करता है। सबसे पहले न्यू बानेश्वर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लगाये गये कफ्यू को, प्रदर्शनकारियों के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश कर जाने के बाद, कफ्यू बढ़ा दिया

गया है और इसमें राष्ट्रपति निवास (शीतल निवास), महाराजगंज, उपराष्ट्रपति निवास (लैनचौर), सिंगदरबार का पूरा क्षेत्र, प्रधानमंत्री निवास (बालुवाटार) और आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। फायरिंग के बाद, गृहमंत्री रमेश लेखक, जो उस समय एक संसदीय समिति की बैठक में थे, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत बैठक से बाहर निकल आए। न्यू बानेश्वर में गोलियां चल रही थीं, और जैसे ही उन्हें सूचना मिली, उन्होंने आपात बैठक बुलाने की जरूरत बताई।

पीलीभीत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) कोई पुष्टि नहीं की है। डीएम पीलीभीत ने बताया कि पीलीभीत से नेपाल के बीच व्यापारिक संबंध होने के कारण यहां के परिवार बड़ी संख्या में नेपाल के महेन्द्र नगर में ही निवास करने के साथ व्यापार भी करते हैं। बड़ी संख्या में वहां की नागरिकता भी उन्होंने ले रखी है।

TRUE VALUE

खरीदे प्री-ओन्ड गाड़ी
1 साल तक की वारंटी के साथ,
सिर्फ TRUE VALUE पर

MARUTI SUZUKI

TRUE VALUE

CELEBRATING
60Lakh
STORIES OF TRUST

376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स

वेरिफाइड कार हिस्ट्री*

1 साल तक की वारंटी और 3 फ्री सर्विस*

यहाँ ऐप डाउनलोड करें।

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruetruevalue.com

AJMER: OPP. SATKAR RESTAURANT NH-8, GAGWANA, JAIPUR ROAD, RELAN MOTORS: 8302722110, 8440041011, 8619237396 | PUSHKAR ROAD, NEAR REGIONAL COLLEGE, AJMER AUTO: 9352091001 | BHILWARA: NEAR GRAM BHARTI, CHITTOR ROAD, BHILWARA, CHAMPION CARS: 9358820044, 9829824128 | 1001/02/03, KIRTI NAGAR, NIMBAHERA ROAD, CHITTORGARH, BHATIA & CO.: 9414059499 | NAGAUR: NAGAUR, MANGALAM MOTORS: 7230055963, 7230055940.

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, जालोर कार्यालय :- जी 1/163, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908